

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला/समाज कल्याण उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 27 अप्रैल, 2016

**विषय:** राज्य में अनचाहे नवजात शिशुओं के लालन-पालन एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "शिशु स्वागत केन्द्र खोले जाने/पालना" (cradle) लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड में लिंग अनुपात अर्थात् 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात (Child Sex Ratio) 2001 में 908 था जोकि 2011 में कम होकर 890 रह गया है। जनपदवार विश्लेषण में यह पाया गया है कि जनपद पिथौरागढ़ में लिंग अनुपात केवल 766 रह गया है। इससे यह स्पष्ट है कि या तो लड़कियों की भ्रूण हत्या की जा रही है या जन्मोपरान्त उन्हें मार दिया जाता है। प्रायः यह भी देखने में आया है कि राज्य में दम्पतियों/अविवाहित महिलाओं द्वारा अनचाहे नवजातों को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से सड़को पर, कूड़ेदानों में या अन्य सुनसान जगहों पर जीवित अवस्था में छोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप उचित देखभाल/चिकित्सीय व्यवस्था के अभाव में उक्त नवजात की मृत्यु हो जाती है। समाज के लिए यह एक अत्यन्त ही कलंकित करने का विषय है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के ऐसे अनचाहे नवजातों के उचित देखभाल करने, उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके लालन-पालन व शिक्षा-दीक्षा हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत "शिशु स्वागत केन्द्र खोले जाने/पालना लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त योजना प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक शिशु सदनों/बाल गृहों एवं जिला चिकित्सालयों/जिला बाल संरक्षण समिति/जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में चलायी जायेगी, जहां पर एक शिशु स्वागत केन्द्र/पालना की व्यवस्था की जायेगी जिसमें अनचाहे नवजातों को रख जा सकता है। उक्त शिशु सदनों/बाल गृहों एवं जिला चिकित्सालयों के माध्यम से सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी को तत्काल दी जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी/सम्बन्धित शिशु सदन के अधीक्षक द्वारा तत्काल नवजात के स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षणोपरान्त नवजात के स्वस्थ न पाये जाने पर स्वस्थ होने तक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के उपरान्त ही समाज

पृष्ठांकन संख्या-303/XVII-2/16-20(म0क0)/2015 तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, समाज कल्याण/महिला कल्याण (महिला कल्याण प्रोबेशन सेक्टर) उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक)
6. मुख्य परीवीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला परीवीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक)
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. आदेश पंजिका।

(डा० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।